फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 02 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 2 अगस्त, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Haryana Takes The Pistols! Maharashtra The Rifles !!...

"With my savings and his salary, we got him a rifle for more than eight lakhs. He also understood that while rifles can cost a lot, it's up to him to shoot well."- Kusale Senior

Top Antioxidant-Rich Foods to Include in Your Diet Regularly

राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसम्बर तक जयपुर में ''राइज़िंग राजस्थान'' इन्वैस्टमैंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया और ''राइज़िंग राजस्थान'' इन्वैस्टमैंट समिट का ''लोगो'' भी लॉन्च किया। इस प्रोग्राम की खास बात यह रही कि लोगो लॉन्च होते ही प्रदेश सरकार को आठ हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हो गये।

'हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था बनाने का है'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिसम्बर में होने वाले राइज़िंग राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक में कहा

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राइज़िंग राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट का ''लोगो'' भी जारी किया।
- मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए सिंगल पॉइन्ट निवेश इन्टरफेस लॉंच किया, जिसके बाद ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन (बी.आई.पी.) को 8,000 करोड़ रूपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राइज़िंग राजस्थान के लिए देश और विदेश में रोड शो भी किए जाएंगे।
- बैठक में उद्योग व वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, सी.आई.आई. के महानिदेशक चंदजीत बनर्जी व अन्य प्रमुख मौजूद थे।

जयपुर, 1 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में 'राइज़िंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में इस संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी-विदेशी कंपनियों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इसी क्रम में आयोजित किए जा रहे इस निवेश सम्मेलन से प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे।

शर्मा ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में आने वाले निवेश को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश संबंधित क्षेत्र की सभी जानकारी पहले ही उपलब्ध करवायी जाए, ताकि उन्हें निवेश को धरातल पर मूर्तरूप देने में आसानी रहे। मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व इस आयोजन से जुड़े समस्त स्टेक हॉल्डर्स को निर्देशित किया कि 'राइज़िंग राजस्थान' निवेश शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान 'राइज़िग राजस्थान' का लोगो भी लॉन्च किया, ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। 'राइज़िंग राजस्थान' के तहत राज्य सरकार देश और विदेश के विभिन्न शहरों में निवेशक रोड शो भी करेगी, ताकि विश्वभर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने का न्यौता दिया जा सके।

साथ ही, राजस्थान में निवेश करने के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 'सिंगल-प्वाइंट निवेशक इंटरफेस' को भी लॉन्च किया, ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से एम.ओ.यू. कर सकें। इस पहल के लॉन्च किये जाने के तुरंत बाद 'राइजिंग राजस्थान' के आयोजन के लिए नोडल विभाग ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को 8000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने से राजस्थान के लिए विकास के नए अवसर खुले हैं। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या भाजपा अब राहुल गांधी व कांग्रेस को वाकई में खतरा मानने लगी है?

आज संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, कल कर्नाटक के भाजपा नेता तेजस्वी सूर्य और परसों अनुराग ठाकुर ने राहुल को अपने मौखिक आक्रमण का टारगैट बनाया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा के लिए वास्तविक खतरे के रूप में उभर चुकी है?

जिस तरह से भाजपा नेता चाहे वे मंत्री हो या सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, उससे तो यही लगता है।

बजट सत्र में संसद ने देखा कि किस तरह भाजपा नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति आक्रामक हो गए और अपशब्दों का प्रयोग किया।

आज लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपा खो बैठे और उन्होंने बार-बार हो रही रेल दुर्घटनाओं के ए सवाल पूछने पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस 58 साल में रेल्वे मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बना सकीं और हमसे दस साल में ही सवाल कर रहे हैं।

उनके भाषण के बीच में कांग्रेस ने वॉक आउट किया क्योंकि वे बार-बार हो रही रेल दुर्घटना पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे।

इससे एक दिन पूर्व बुधवार को भाजपा के कर्नाटक सांसद तेजस्वी सूर्या के जरिए भाजपा ने राहुल पर हमला करवाया। उन्होंने वायनाड में हुए भूस्खलन के लिए राहुल पर निशाना साधा कि वे अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र और उसकी समस्याओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं।

इसके एक दिन पहले भाजपा नेतृत्व ने अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी पर हमला करने के लिए मैदान में उतारा था।

जवाहर लाल नेहरू से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक और अब राहुल सभी को अपशब्द बोलने व अपमानित करने का भाजपा का तरीका एक जैसा है।

भाजपा नेतृत्व संभवतया मानता है कि गांधी परिवार को गाली देने और अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने से उनकी संभावनाएं फिर से बेहतर हो जाएगी और विभिन्न सामाजिक समूह फिर से भाजपा के खेमे में आ जाएंगे।

सोशल मीडिया का एक बड़ा भाग राहुल गांधी के समर्थन में उतर आया है और उन्हें विभिन्न वर्गों से उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है।

जिस तरह से राहुल जातिगतत जनगणना के मुद्दे पर नरेन्द्र मोदी और भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं और विभिन्न जातियों को सत्ता में भागीदारी देने की बात कर रहे हैं उसकी सभी तारीफ कर रहे है।

मंडल आयोग के प्रति राजीव गांधी के विरोध और जवाहर लाल नेहरू के आरक्षण विरोध को मुद्दा बनाया जा रहा है जो अतीत की बाते हैं, जिनका अब खास महत्व नहीं रहा है।

उक्त वरिष्ठ नेता ने कुहा कांग्रेस 2014 में इसीलिए 44 तक पहुंच गई थी। भाजपा भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ भाजपा इतनी आक्रामक है।

- भाजपा शायद महसूस कर रही है कि जवाहर लाल नेहरू के आरक्षण विरोधी रवैये व राजीव गांधी के मण्डल आयोग विरोधी विचार पर फोकस करके वो राहुल गांधी के, जात/जाति आधारित जनगणना के नारे की हवा निकाल देगी। पर, ऐसा होता नहीं दिख रहा। अधिकांश सोशल मीडिया नेहरू व राजीव के आरक्षण विरोधी विचारों को पुरानी बात बता कर मूलतः राहुल गांधी के पक्ष में खड़ा है।
- अनुराग ठाकुर के बाद, कल सांसद तेजस्वी सूर्य ने राहुल को टारगैट बनाया, यह कह कर कि उन्होंने वायनाड की ''लैण्ड स्लाइड'' की गंभीर स्थिति पर कभी ध्यान नहीं दिया और खतरे पर कभी फोकस नहीं किया।
- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कांग्रेस द्वारा रेल दुर्घटना का मुद्दा उठाने पर आक्रामक रूख अपनाया और कहा कि कांग्रेस ने अपने 58 साल के कार्यकाल में ''रेलवे मॉनिटरिंग सिस्टम'' तक नहीं लगवाया और हमने दस साल में यह जिम्मेवारी पूरी की।

जयपुर में 12वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश

जयपुर, 1अगस्त। राजधानी जयपुर में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने दो अगस्त को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलैक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देशानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने इस संबंध में देर रात आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक जयपुर शहर में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्र-छात्राओं का दो अगस्त को अवकाश रहेगा। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को इस आदेश की पालना करने को कहा है।

- शहर में भारी बारिश और पानी भरने को देखते हुए जिला कलैक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए।

राहुल गांधी अमेरिका जायेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। राहुल गांधी सितम्बर के प्रारंभ में अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं।

वहाँ उनके कई राज्यों में जाने तथा भारतीय समुदाय के लोगों तथा उद्योगपतियों से मिलने की संभावना है। इसके अलावा, वे भारत के अन्य हितचिन्तकों से भी मिल सकते हैं।

जिन नगरों में उनका जाना विचाराधीन हैं, वे हैं- वॉशिंगटन, शिकागो, डैट्रॉयट, डालास, सैन फान्सिस्को, लॉस एन्जिल्स आदि।

उनकी यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रुप दिये जाने पर अभी विचार चल रहा है।

अमेरिका के बहुत सारे संस्थान अब उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि अब वे विपक्ष के नेता हैं तथा अनेक मुद्दों पर मोदी सरकार का मुकाबला कर रहे हैं।

अमेरिका में नवम्बर में चुनाव होने हैं, इसलिये मुख्य सवाल यह भी है कि क्या वहाँ चुनाव के बाद जाना बेहतर रहेगा।

लेकिन चूँकि यह सरकारी यात्रा नहीं है तथा पहले के कई अवसरों की तरह, राहुल की तरफ भारत तथा अमेरिका दोनों ही देशों के मीडिया का विशेष ध्यान रहेगा।

- सितम्बर के अंत में प्रस्तावित है यह यात्रा। जैसा कि विदित ही है, नवम्बर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हैं।

'जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम से जी.एस.टी. हटाएं'

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 अगस्त। भाजपा के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री सड़क, परिवहन व राजमार्ग, नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से जीवन व मैडिकल बीमा की किश्त पर लगने वाले 18 प्रतिशत वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) को समाप्त करने का अनुरोध किया है। इस कर के बारे में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यह कर लगने से जीवन की अनिश्चितताओं पर व्यक्तिगत भार में वृद्धि होती है तथा इसकी वजह से इस क्षेत्र की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है।

28 जुलाई को सीतारमन को लिखे पत्र में गडकरी ने उनके अनुरोध को वरियता देने का अनुरोध किया और विशेष रूप से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कर काफी मुश्किल वाला है। उन्होंने इस बारे में कहा कि लाइफ व मैडिकल इंश्योरेन्स के प्रीमियम पर लागू जी.एस.टी. की वर्तमान दरें उद्योगों के विस्तार में रूकावट पैदा कर रही हैं तथा समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं।

गडकरी ने यह अपील नागपुर के डिविज़नल जीवन बीमा निगम की कर्मचारी यूनियन की ओर से इस मामले पर ज्ञापन मिलने के बाद जारी की है। इस ज्ञापन में बीमा सैक्टर द्वारा वहन की जा रही मुश्किलों के बारे में चिन्ता प्रकट की गई है।

नागपुर से सांसद होने के बतौर गडकरी ने उनकी बातों को जोर देकर उठाया है और कहा है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर कर लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह उन लोगों पर नहीं लगना चाहिए जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे कराते हैं।

इसके अतिरिक्त गडकरी ने जीवन बीमा के माध्यम से होने वाली बचत के साथ असमान व्यवहार का मुद्दा भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री से अपील की।

मु.मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपए की सहायता देने की घोषणा की

जयपुर, 1 अगस्त (का.सं.)। जिले में हुई तेज बारिश से वीकेआई क्षेत्र में तीन लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। वहीं, प्रदेश में तेज बारिश की वजह से बने हालातों पर निगरानी रखने और तुरंत प्रभाव से सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वी.के.आई. क्षेत्र में तीन लोगों की बेसमैंट में डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई और नकद सहायता देने की घोषणा की।

एस.सी-एस.टी. आरक्षण में उप जाति आधारित सब कैटगराइज़ेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि राज्यों सरकारों को जातीय आधार पर एस.सी. आरक्षण कोटा के वर्गीकरण का अधिकार है

नई दिल्ली, 1 अगस्त (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम 2006 को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरियों और शैक्षिणक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए शैड्यूल कास्ट (एस.सी.) और शैड्यूल ट्राइब्स (एस.टी.) का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की संविधान बैंच ने छः-एक के बहुमत वाले अपने फैसले में पंजाब के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इस तरह के उप-वर्गीकरण के लिए कानून की वैधता को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने बहुमत से असहमति वाला फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह का उप-वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को एससी आरक्षण में भी जातीय आधार पर उसके वर्गीकरण का आधार है। यह आरक्षण उन जातियों के लिए अलग से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो पिछड़ी रह गई हों और उनसे ज्यादा भेदभाव किया जा रहा हो। यही नहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि किसी भी कैटिगरी में पहली पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससी और एसटी में आरक्षण का वर्गीकरण करना उचित विचार है।

जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गई है या नहीं। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस अहम केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में समरूपता नहीं है। इसमें भी विभिन्नताएं हैं। हालांकि 7 जजों की बेंच में अकेले जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की राय अलग थी। उनका कहना था कि अनुसूचित जाति वर्ग को जाति नहीं बल्कि क्लास के आधार पर आरक्षण मिलता है।

वहीं जस्टिस मिथल ने कहा कि आरक्षण किसी भी वर्ग में पहली पीढी को ही मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरी पीढ़ी को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सिस्टम में भेदभाव के चलते एससी और एसटी वर्ग ऊंचाई हासिल नहीं कर सका। लेकिन संविधान का आर्टिकल 14 उप-वर्गीकरण की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि उपेक्षित वर्ग में भी विभिन्नताएं रही हैं और उन्हें अलग-अलग सामाजिक परिस्थितियों में रहना पड़ा है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 25 जातियों में से 9 ही एससी में हैं। हमने यह भी देखा है कि इस वर्ग में भी समरूपता नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि किसी भी कैटगरी में पहली पीढ़ी को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एस.सी. और एस.टी. में आरक्षण का वर्गीकरण करना उचित विचार है।
- जस्टिस पंकज मिथल ने कहा कि इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य वर्ग के स्तर पर आ गई है या नहीं। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए।